हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों का विकास

3060. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी-कुल्लु राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लु शहर के निकट "बाईपास" बनाने तथा ब्यास नदी पर कुछ पुलों के निर्माण संबंधी प्राक्कलन भारत सरकार को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राक्कलन किस तारीख को भेजे गये हैं; और

(ग) उपरोक्त योजनाओं में से किन-किन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और कौन-कौन सी योजनायें लम्बित हैं, और इन लम्बित योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) रा० रा०-21 पर कुल्लु से निकट बाईपास तथा ब्यास नदी पर दो पुलों के निर्माण से संबंधित सम्पूर्ण प्रस्ताव हिमाचल सरकार ने दिनांक 17-10-91 को भेजा था । इस प्रस्ताव में 20.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2 लेन वाला एक बाईपास बनाने की परिकल्पना की गयी है । चूंकि स्कीम की जांच की जा रही है, इसलिए अभी से यह बताना संभव नहीं है कि किस तारीख तक इसे अनुमोदन दे दिया जाएगा ।

Kilometer Scheme for Red Line Bus Service

3061. SHRIMATI KAILASHPATI : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the Committee on Public Undertakings has in their 22nd report on DTC recommended that Red Line Bus Services should be converted into Cash Carry to Kilometer Scheme; and

(b) if so, what is the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Inter-State Transport Service from Kashmir to Kanyakumari

3062. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to develop Surface Transport to various States to spread the cultural heritage of each State; and

(b) if so, the measures contemplated to ply Inter-State Surface Transport from Kashmir to Kanyakumari ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) There is no such proposal before the government.

(b) Does not arise.

मंडी और रोहतांग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति

3063. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री सुशील बरोंगपा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी में आयी बाढ़ के फलस्वरूप मंडी और रोहतांग दर्रे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाढ़ के फलस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई है और इसकी क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां । मन्डी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ।

(ख) राज्य सरकार से क्षति के कुल ब्यौरे और इसकी मरम्मत के प्राक्कलन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । इसी बीच तदर्थ आधार पर अब तक 50 लाख रुपए की राशि दी गई है ।

अन्तर्राज्यीय पर्यटक बसों को जारी किए गए परमिट

3064. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान पैकेज टूअर प्रोग्रामों के अधीन मध्य प्रदेश की पर्यटक बसों को राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यात्राओं के लिए राज्य स्तर पर एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितने परमिट जारी किये गए;

(ख) इन परमिटों के जरिये शासन द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ग) इस तरह की पर्यटक बसों के लिए परमिट प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं वसूले जाने वाले टैक्स का ब्यौरा क्या है ?

जल-परिवहन परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों सहित सभी प्रकार के परमिट राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा रहे हैं । अत: सूचना मध्य प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

Indian Shipyards on the Verge of Closure

3065. SHRI SHIV CHARAN SINGH :
SHRI NARAIN PRASAD GUPTA :
Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Shipyards are on the verge of closure, if so, the details thereof;

(b) what steps are intended to be taken by the Government during the Eighth Five Year Plan to save the closure of Indian Shipyards, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that if 10 per cent of the country's ships be built in our shipyards during the Eighth Plan, it will help to save the Indian Shipyards from closure, if so, the Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) No, Sir.

(b) The following steps are under consideration for revival of Indian Shipyards constructing ocean-going merchant vessels :—

(i) The price of an ocean-going vessel built at Indian Yards be fixed on the basis that the public sector yard would participate in open tender and be permitted to match the lowest bid and thereafter be entitled to 30% extra price over the above price—20% being payable by the Government and 10% by the shipowner.

(ii) Loans at concessional rates of 9% to the extent of 80% of the cost of a ship may be given to Shipping Companies placing orders with Indian Yards.

(iii) Fixation of price in terms of US $/ Japanese Yen and the shipowners to pay each stage instalment to the shipyard at market determined parity rate of foreign exchange prevailing on the date of actual payment.

(iv) The subsidy to be released by Govt. will be paid alongwith the payments received by the shipyards for stage payments as per prevailing market determined date of exchange.

(c) As mentioned in reply to part (a), the Indian Shipyards are not on the verge of closure. Hence, the question of reserving 10 per cent of country's ships to be built in our Yards, does not arise.

———

12-00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. **Accounts (1989-90) of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation, Bhopal and related papers.**

II. **Memorandum of Understanding (1993-94) between Government of India and the Central Inland Water Transport Corporation Limited.**

III. **Notifications of the Ministry of Surface Transport (Ports Wing).**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Audited Accounts of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation, Bhopal, for the year 1989-90, under sub-section (4) of section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950, read with sub- clause (iv) of clasuse (c) of the Proclamation dated 15th December, 1992 issued by the President in relation to the State of Madhya Pradesh.

(b) Review by Government of the Annual Accounts.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-4308/93].

II. Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Surface Transport) and the Central Inland Water Transport Corporation Limited for the year 1993-94.

[Placed in Library. *See* No. LT-4307/93].

III. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Surface Transport (Ports Wing), under sub-section (4) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 :—